वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) चीनी उद्योग में अवैध आय की उत्पत्ति के बारे में राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान द्वारा किए जा रहे विस्तृत अध्ययन का इन्तजार किया जा रहा है । संस्थान की रिपोर्ट में किए गए प्रस्तावों पर सरकार की प्रतिक्रिया, सार्वजनिक बहस के समाप्त होने और सुझावों के मिलने के बाद ही दीर्घकालीन वित्तीय नीति में अभिव्यक्त की जायेगी ।

राज्यों को ओवर-ड्राफ्ट भुगतान

1871. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके संबंध में मार्च, अप्रैल, 1985 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ओवर ड्राफ्ट भुगतानों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि रिजर्व बैंक और महालेखाकार की भूलों के कारण कुछ दूसरे राज्यों के भुगतानों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) रिजर्व बैंक और महालेखाकार की इस भूल के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में ऐसी भूले नहीं हों, क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा एक राज्य विशेष को स्वीकृत एक बड़ी धनराशि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गलती से किसी दूसरे राज्य के खाते में हस्तांतरित कर दिया गया था, यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी): (क) भारत सरकार ने राज्यों को सलाह दी थी कि यदि वे निरन्तर सात कार्य दिवसों से अधिक के लिए 28-1-85 के अपने ओवर-ड्राफ्ट की सीमाओं से अधिक ओवर-ड्राफ्ट में रहते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक उनके भुगतानों को बंद कर देगा । उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश ने क्रमशः फरवरी और अप्रैल; 1985 में इन स्तरों को पार कर लिया था और प्रत्येक के भुगतान एक दिन के लिए रोक दिए गए ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने और किसी राज्य का भुगतान बंद नहीं किया ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

खाद्यान्नों के भंडारण के लिए बैंक ऋण

1872. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 27 जून, 1985 को "दि टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि लगभग 3 करोड़ मीटरी टन खाद्यानों के भण्डारण के लिए लगभग 8 हजार करोड़ रुपए के बैंक ऋण की धनराशि अंतर्ग्रस्त है जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंच रहा है; और

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी हां ।

गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र की एजेंसियों अर्थात् भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों/उनकी एजेंसियों के

नाम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया खाद्य ऋणों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रुपए)

के अंतिम शुक्रवार के दिन	बकाया राशि
जून, 1983	3589
जून, 1984	5238
जून, 1985	6754

हाल के वर्षों में खाद्य ऋणों में वृद्धि मुख्यत: अनाज के स्टाक के मूल्य में वृद्धि के अनुरूप ही है। खाद्य ऋणों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति बैंकों के लिए चिंता का विषय नहीं है क्योंकि ये अग्रिम प्रतिभूत होते है और इनसे बैंको को आमदनी होती है।

Report by World Bank

1873. SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have taken note of the World Development Report, 1985 (World Bank Report);

(b) whether report criticises the developing countries particularly India, for its slow progress in its development in spite of re-scheduling of debts; and

(c) if so, what measures Government propose to take to meet the criticism contained in the Report of the World Bank?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) Yes, Sir.

(b) The World Development Report 1985 focuses on the role of international capital in economic development and in this context it has dealt with the various factors which have contributed to the recent debt problems faced by many developing countries. The report has however singled out India for appreciation under the heading: "Careful Borrowing and Risk avoidance; The case of India". In treating re-schedulings which had occurred prior to recent debt problems, a reference is made to India, but the report makes it clear that the then re-scheduling for India was designed by donors to enhance their aid volume. The report also points out that though growth in recent years has slowed, most developing countries had made substantial economic progress over the past twenty years. Thus there is no implicit or explicit criticism of India's economic performance in the report.

(c) Does not arise.

News item captioned 'Bogus Banks loan cases detected'

1874. SHRI BISWA GOSWAMI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a news item captioned 'Bogus bank loan cases detected' which appeared in the "Economic Times", New Delhi on the 21st June, 1985;

(b) if so, what are the details in this regard; and

(c) what action has been taken against the persons involved in this fraud?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) to (c) Yes, Sir. The allegation mainly refers to fraudulent activities in advancing crop loans. No specific banks or borrower has been mentioned in the news tiem. However, Reserve Bank of India has been asked to get the matter investigated.

Visit by a team of Agricultural Bank of China

1875. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether a team of officers from Agricultural Bank of China visited India in the third week of June, 1985; and